वाराणसी एससीओ की पहली 'सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी'

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच- उनकी संरचना और अधिदेश

संदर्भ

- भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्ता का घोतक वाराणासी को "शंघाई सहयोग संगठन" (एससीओ) की पहली 'सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी' घोषित किया जायेगा।
- भारत ने 2 नवंबर, 2019 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया था।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

एससीओ की पहल

- 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन से पहले संगठन की नयी पहल पर प्रकाश डाला गया है।
- नयी पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद प्रभावी होगा, जिसके बाद भारत अध्यक्षता का पदभार संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- एससीओ के महासचिव ने नयी पहल के तहत वारणसी को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है।
- भारत में सबसे पहले यह खिताब भारत के प्राचीन शहर वाराणसी को प्रदान किया जाएगा।

- इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष क्रमश: सदस्य देश के किसी सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को, अध्यक्षता प्रदान करेंगे, जिससे उसका महत्व बढ़ेगा।

एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद का 19वां शिखर सम्मेलन और भारत

- उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 30 नवंबर को वर्चुअल प्रारूप में भारत द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
- विदित है कि वर्ष 2017 में संगठन की पूर्ण-सदस्यता प्राप्त करने के बाद, यह पहली बार था, जब भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की गई। यह शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन के प्रधानमंत्रियों के स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और मुख्य रूप से संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे से संबंधित होता है।
- भारत ने 2 नवंबर 2019 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया तथा एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद (सीएचजी) के 19वें सत्र की मेजबानी करके 30 नवंबर 2020 को अपना वर्ष भर का कार्यकाल पूरा करेगा।

एससीओ का 19वां शिखर सम्मेलन और भारत

- भारत ने सम्मेलन में तीन स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया-
    1. स्टार्टअप और नवाचार
    2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
    3. पारंपरिक चिकित्सा

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

- पृष्ठभूमि
    - एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
    - शंघाई सहयोग संगठन के निर्माण की घोषणा जून 2001 में शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, उज़्बेकिस्तान गणराज्य, रूसी संघ और ताजिकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई थी।

- जून 2017 में अस्ताना में आयोजित एससीओ के राज्य परिषद के प्रमुखों की ऐतिहासिक बैठक में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

- एससीओ के सदस्य देश
  - चीन
  - भारत
  - कजाखस्तान
  - किर्गिज़स्तान
  - रूस
  - पाकिस्तान
  - तजाकिस्तान
  - उज़्बेकिस्तान
  - ईरान

पूर्ण सदस्यता हेतु रुचि रखने वाले 3 पर्यवेक्षक राज्य	
1.	अफगानिस्तान
2.	बेलारूस
3.	मंगोलिया
4.	ईरान

डायलॉग पार्टनर	
1.	आर्मीनिया
2.	अज़रबैजान
3.	कंबोडिया
4.	नेपाल
5.	श्रीलंका
6.	टर्की

- राज्य परिषद के प्रमुख
  - यह एससीओ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
  - यह वर्ष में एक बार मिलते हैं और संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय और दिशा-निर्देश को संबोधित करते हैं।
  - यह संगठन की बहुपक्षीय सहयोग रणनीति और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करने, वर्तमान महत्वपूर्ण आर्थिक और अन्य सहयोग मुद्दों को हल करने और संगठन के वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए एससीओ प्रमुखों की सरकार परिषद (एचजीसी) वर्ष में एक बार मिलती है।
  - एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं।

- स्थायी निकाय
  - संगठन के दो स्थायी निकाय हैं-
  - बीजिंग में स्थित एससीओ सचिवालय
  - ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) की कार्यकारी समिति।

- एससीओ के मुख्य लक्ष्य
  - सदस्य देशों के मध्य आपसी विश्वास और पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ करना

- व्यापार, राजनीति, अनुसंधान, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
- शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन और अन्य क्षेत्र में सहयोग
- क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और शांति बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना
- एक लोकतांत्रिक, तर्कसंगत और निष्पक्ष नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की ओर बढ़ना।
- संगठन आपसी लाभ, विश्वास, परामर्श, समानता, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान और सामान्य विकास की इच्छा के सिद्धांतों के आधार पर अपनी आंतरिक नीति का अनुसरण करता है, जबकि बाहरी नीति गैर-लक्षित और गैर-संरेखण है।

शंघाई सहयोग संगठन का महत्व

- यह वैश्विक आबादी का 40%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% और विश्व के 22% भूमि द्रव्यमान को कवर करता है।
- अपने भौगोलिक महत्व के कारण एशिया में एससीओ की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। यह इसे मध्य एशिया को नियंत्रित करने और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम बनाता है।
- एससीओ को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है।

एससीओ का भारत के लिए महत्व

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में चीन, रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है।
- भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। एससीओ को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है।
- भारतीय हितों के लिए विद्यमान चुनौतियां- आतंकवाद, ऊर्जा की आपूर्ति, प्रवासन मुद्दा आदि भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम हैं। फलतः ऐसे में एससीओ और भारत दोनों एक-दूसरे के लिए लाभप्रद हैं।

स्रोत: द हिन्दू

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2022

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** महत्वपूर्ण नीतियाँ और हस्तक्षेप, शिक्षा

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2022 प्रकाशित की है।
- विदित है कि आईआईटी-मद्रास ने इस वर्ष भी समग्र शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में पहला स्थान बनाए रखा है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

एनआईआरएफ रैंकिंग 2022

- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग श्रेणियां:
  - 11 श्रेणियों के लिए एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2022 की घोषणा की गई है।
  - इसमें समग्र, विश्वविद्यालय, प्रबंधन, कॉलेज, फार्मेसी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, एआरआईआईए (नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग), कानून और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।
- मूल्यांकन
  - रैंकिंग ढांचा मानकों के पांच व्यापक सामान्य समूहों पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है।
  - शिक्षण, सीखना और संसाधन (टीएलआर), अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (आरपी), स्नातक परिणाम (जीओ), आउटरीच और समावेशिता (ओआई) और धारणा (पीआर)।

- मापदंडों के इन पांच व्यापक समूहों में से प्रत्येक के लिए दिए गए अंकों के कुल योग के आधार पर रैंक दी जाती है।

- समग्र श्रेणी
  - समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, उसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है।
- विश्वविद्यालय श्रेणी
  - विश्वविद्यालयों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) ने पहला स्थान, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नयी दिल्ली ने दूसरा स्थान और जामिया मिलिया इस्लामिया ने तीसरा स्थान हासिल किया।
  - एनआईआरएफ रैंकिंग में पिछले वर्ष इस श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की रैंकिंग इस साल छठे स्थान पर चली गई।
- इंजीनियरिंग संस्थानों की श्रेणी
  - इंजीनियरिंग संस्थानों की श्रेणी में आठ आईआईटी ने शीर्ष 10 में जगह बनाई।
  - इसमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बम्बई क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- कालेज श्रेणी
  - कालेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस ने पहला स्थान, हिंदू कॉलेज ने दूसरा स्थान और प्रेसीडेंसी कॉलेज ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
  - शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय रैंकिंग में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज तथा चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को सर्वश्रेष्ठ डेंटल कॉलेज घोषित किया गया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत में टीकाकरण रहित बच्चों में वृद्धि

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण नीतियाँ और हस्तक्षेप

संदर्भ

- हाल ही में, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण डिप्थीरिया-टेटनस-पर्टुसिस संयुक्त टीके की पहली खुराक से वंचित या छूटे हुए बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है।
- विदित है कि यह संख्या 2019 में 1.4 मिलियन से बढ़कर 2021 में 2.7 मिलियन हो गई है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- लगभग 30 वर्षों में बाल्यावस्था के टीकाकरण में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
- डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DTP3) के खिलाफ टीके की तीन खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत वर्ष 2019 और 2021 के बीच 5 प्रतिशत अंक गिरकर 81 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2021 में नियमित टीकाकरण सेवाओं के माध्यम से 25 मिलियन बच्चे डीटीपी की एक या अधिक खुराक लेने से चूक गए।
- विदित है कि यह 2020 की तुलना में 2 मिलियन अधिक और 2019 की तुलना में 6 मिलियन अधिक है।

टीकाकरण में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक

- संघर्ष और संवेदनशील वातावरण में रहने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि, जहां टीकाकरण की पहुंच अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है।
- कोविड-19 से संबंधित मुद्दे जैसे कि सेवा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए संसाधन डायवर्जन और रोकथाम के उपाय, जो सीमित टीकाकरण सेवा की पहुंच और उपलब्धता को सीमित करते हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत में प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1978 में ' प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम ' (EPI) के रूप में शुरू किया गया था।
- 1985 में, कार्यक्रम को 'सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम' (यूआईपी) के रूप में संशोधित किया गया था, जिसे 1989-90 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था।
- गत कई वर्षों से संचालित होने के बावजूद यूआईपी अपने पहले वर्ष में केवल 65% बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करने में सक्षम हुआ।

मिशन इंद्रधनुष

- मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था।
- मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है।
- विदित है कि पहले पूर्ण टीकाकरण कवरेज में वृद्धि 1% प्रति वर्ष थी, जो कि मिशन इंद्रधनुष के पहले दो चरणों के माध्यम से बढ़कर 6.7% प्रति वर्ष हो गई है।
- अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के चार चरणों का संचालन किया गया और 2.53 करोड़ से अधिक बच्चों और 68 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।

गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई)

- आईएमआई को अक्टूबर 2017 में टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने के लिए लॉन्च किया गया था।
- सघन मिशन इंद्रधनुष दरअसल विशेष टीकाकरण अभियान है। यह दो वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती, जो नियमित टीकाकरण से छूट जाते हैं। विशेष अभियान चलाकर उन्हें टीके लगाए जाते हैं।
- दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने के लिए विशेष अभियान का संचालन किया गया था।
- फरवरी 2022 में, सरकार ने गहन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0 लॉन्च किया।
- IMI 3.0 को 2021 में उन सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिन्होंने कोविड -19 महामारी के दौरान अपने टीके की खुराक लेने से चूक गए थे।

उपलब्धियां

- अब तक, देश भर के 701 जिलों को कवर करते हुए मिशन इंद्रधनुष के दस चरणों को पूरा किया जा चुका है।
- अप्रैल 2021 तक मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
- मिशन इंद्रधनुष के पहले दो चरणों के परिणामस्वरूप एक वर्ष में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7% की वृद्धि हुई।
- हालांकि, हाल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि एनएफएचएस-4 की तुलना में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 18.5% अंक की वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) -3 (2005-2006) के दौरान कवरेज 43% से बढ़कर एनएफएचएस -4 (2015 - 2016) में 62% हो गया।
- एनएफएचएस-5 में, एनएफएचएस-4 में 62 प्रतिशत की तुलना में 12-23 महीने की उम्र के तीन-चौथाई (77%) से अधिक बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया था ।

स्रोत: द हिन्दू